RNI NO. PUNBIL/2014/59416

UTURNTIME.COM

यूटर्न टाइम

THE GOOD, BAD AND UGLY OF INDIA

FOLLOW US ON @UTURNTIMENEWS

पेज 07

बिकिनी में नजर आई इशन्या माहेश्वरी

VOL: 03 | ISSUE 181 | FRIDAY DATE 24-07-2026 | RS 3 | PAGE-8 | PUBLISHED BY: DELHI | HINDI DAILY NEWSPAPER Visit at : www.uturntime.com

संक्षिप्त खबरें

पेपर लीक की जिम्मेदारी भी लें मोदी : प्रियंका

नयी दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई । कांग्रेस महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि 152 पेपर लीक होने के बावजूद किसी को सजा नहीं मिली और इसकी जिम्मेदारी श्री मोदी को लेनी चाहिए। श्रीमती वाड्रा ने गुरुवार को संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि देश के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार के सांसद ही संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसद चलाने में विफल रही है और युवाओं की जायज मांगों को दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर उपलब्धि का श्रेय लेते हैं लेकिन पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। उनका कहना था कि 152 पेपर लीक होने के बावजूद किसी दोषी को सजा नहीं मिली, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए।

उपराज्यपाल ने स्कूलों की सुरक्षा में भविष्योन्मुखी नजरिया अपनाने पर दिया जोर

नई दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई । दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) टीएस संधू ने गुरुवार को स्कूल की सुरक्षा और मजबूती के लिए एक व्यापक और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखने वाले नजरिए की जरूरत पर जोर दिया।

संधू ने पीएचडी हाउस में 'सेफ स्कूल्स लीडरशिप 2026' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आज स्कूल सुरक्षा का दायरा सिर्फ भौतिक बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें साइबर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और आपदा की तैयारी भी शामिल है।

उपराज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का मकसद ऐसा माहौल बनाना है जहां युवा मन सीख सकें, आगे बढ़ सकें और अपनी क्षमता को पहचान सकें; यह प्रक्रिया सुरक्षा की बुनियादी भावना के बिना संभव नहीं है। इस दौरान एलजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन शब्दों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'शिक्षा केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम है।' उपराज्यपाल ने कहा कि इस सोच को तभी साकार किया जा सकता है जब हर बच्चे को सुरक्षित और बेहतर माहौल में सीखने का अवसर मिले। इस मौके पर संधू ने 'नेशनल मॉडल स्कूल सेफ्टी टूलकिट' भी लॉन्च की। उन्होंने इसे स्कूलों में बचाव और तैयारी की संस्कृति को संस्थागत बनाने की दिशा में एक अहम कदम बताया। एलजी ने स्कूल लीडर्स से कहा कि वे सुरक्षा को सिर्फ नियमों को पूरा करने की जरूरत न समझें, बल्कि इसे संस्थागत नेतृत्व का एक जरूरी हिस्सा मानें।

दिल्ली को स्वच्छ-सुंदर बनाना हमारी प्राथमिकता: रेखा गुप्ता

» **नयी दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई ।**

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में 'डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन' परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल कचरा उठाना नहीं, बल्कि एक आधुनिक, तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। यह नयी व्यवस्था घर-घर से कचरा संग्रहण को अधिक प्रभावी, समयबद्ध और जवाबदेह बनायेगी तथा स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। उन्होंने कहा कि पहले नगर निगम के समक्ष पर्याप्त संसाधनों और आधुनिक उपकरणों का अभाव था।

□ दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पश्चिमी दिल्ली में डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना स्वच्छता व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कचरा संग्रहण वाहनों की कमी, जर्जर ढलाव और सीमित मशीनरी के कारण स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती थी।

अब इन कमियों को दूर करते हुए आधुनिक कम्पैक्टर युक्त ट्रांसफर स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जो न केवल तकनीकी रूप से सक्षम हैं बल्कि देखने में भी आकर्षक हैं। यह व्यवस्था केवल पश्चिमी दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से पूरी दिल्ली में लागू की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ, हरित और विकसित दिल्ली का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी से ही संभव है। उन्होंने नागरिकों से घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था का सहयोग करने, गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का आ'ान किया।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक तकनीक, मजबूत बुनियादी ढांचे और जनसहभागिता के समन्वय से दिल्ली देश की सबसे स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित राजधानी के रूप में स्थापित होगी। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पश्चिमी दिल्ली में डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना स्वच्छता व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के माध्यम से घर-घर से समयबद्ध कचरा संग्रहण, आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी और बेहतर शिकायत निवारण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में स्वच्छ, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आधुनिक वाहनों, स्मार्ट मॉनिटरिंग और बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से पश्चिमी दिल्ली के लाखों नागरिकों को बेहतर स्वच्छता सेवाओं का लाभ मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब घरों से कचरा केवल एक बार नहीं, बल्कि सुबह और शाम, दिन में दो बार उठाया जाएगा।

पेपर लीक के दोषियों को जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे: मोदी

» **नयी दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई ।**

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे व्यापक प्रदर्शनों के बीच सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वयं इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, मामले के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा।

गुजरात में बारिश का कहर, पीएम मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात, हर संभव मदद का भरोसा

गांधीनगर, यूटर्न/ 23 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच बाढ़ प्रभावित वलसाड जिले के लिए एनडीआरएफ की दो और टीमें दिल्ली से हवाई मार्ग से भेजी गई हैं। फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री ने भारी बारिश से हुए नुकसान और चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों की जानकारी ली।

नीट मुद्दे पर सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए है तैयार : नितिन नवीन

» **नयी दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई ।**

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष दलों को नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा करने की चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

श्री नवीन ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि जैसे ही वे सदन में आएंगे, देश की जनता और युवाओं के सामने उनका दोहरा चरित्र पूरी तरह से उजागर हो जाएगा।

उन्होंने कहा, 'हम पूरे विपक्ष को खुली चुनौती देते हैं। आइए, सदन में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) समेत छात्रों और युवाओं से जुड़े हर मुद्दे पर खुली चर्चा करें।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार हर विषय पर बातचीत करने और हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।' उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी और विपक्ष का राजनीतिक इतिहास चर्चा से बचने का रहा है। इसीलिए, सदन में बहस का सामना करने के बजाय वे इससे भागते हैं।

सरकार युवाओं के भविष्य और हितों की रक्षा करने के लिये प्रतिबद्ध : नड्डा

» **नयी दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई ।**

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार युवाओं के भविष्य और हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नड्डा ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, 'पेपर लीक जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का श्री मोदी का संकल्प, युवाओं के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।'

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके विपरीत विपक्ष और उसके नेता श्री गांधी संसद में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सार्थक चर्चा करने से बच रहे हैं। विपक्षी दल इसके बजाय सड़कों पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत उनके गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।

आस्थावान बनने का ठेका ले रहे आस्था पर प्रहार करने वाले : योगी

» **गोरखपुर, यूटर्न/ 23 जुलाई ।**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था, सुरक्षा व विकास के मुद्दे पर कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने के दौरान आस्था पर प्रहार करने वाले सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले रहे हैं। कांग्रेस व सपा के लोगों के मुंह से आस्था के उपदेश हास्यास्पद लगते हैं। सपा ने अपने शासन में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में बाधा डाली, रामभक्तों पर गोली चलवाई। कांग्रेस ने भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, मंदिर आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा किया। ये लोग किस मुंह से आस्था की बात कर रहे हैं? सीएम योगी गुरुवार को गोरखपुर जिले के पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के उपरांत जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उक्त विकास कार्यों में टीपीनगर-पैडलेगंज मार्ग पर 2.6 किमी लंबे सिक्सलेन फ्लाईओवर सहित 813.52 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-सपा ने अपनी सरकारों में न केवल आस्था से खिलवाड़ किया.

अगर मेट्रो स्टेशन बंद रहने का मामला नहीं सुलझा, तो कोर्ट दखल देगा: सीजेआई

» नयी दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई ।

उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने गुरुवार को शीर्ष अदालत का ध्यान जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बंद होने की ओर दिलाया। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वकीलों, मुकदमों से जुड़े लोगों, रजिस्ट्री कर्मचारियों और उच्चतम न्यायालय में प्रवेश के लिए वैध पास रखने वाले अन्य लोगों को स्टेशन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने यह मामला रखते हुए श्री सिंह ने सुझाव दिया कि जिन

लोगों के पास उच्चतम न्यायालय में प्रवेश के लिए वैध पास है और जो रजिस्ट्री के कर्मचारी हैं, उन्हें उचित सुरक्षा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति दी जाए।

श्री सिंह ने कहा, 'मेट्रो में एक फायदा है। जब यात्री उतरते हैं, तो एक तय एग्ज़िट पॉइंट होता है जहां सुरक्षा जांच की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट प्रॉक्सिमिटी कार्ड रखने वालों और रजिस्ट्री स्टाफ को वहां से निकलने की इजाजत दी जा सकती है जबकि बाकी यात्रियों को ट्रेन में ही बने रहने और अगले स्टेशन तक जाने के लिए कहा जा सकता है।

इससे यह पक्का हो जाएगा कि अदालत में जाने के लिए अधिकृत लोगों के लिए मेट्रो चलती रहे।' इस बात पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय प्रशासन ने इस मुद्दे पर मेट्रो अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर मामले का समाधान नहीं हुआ तो वह खुद इसमें दखल देंगे।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के सामने यह मुद्दा पहले ही उठा दिया है और आशा व्यक्त की है कि शीघ्र ही इसका समाधान हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वह खुद इसमें दखल देंगे। उन्होंने बताया कि सिंह के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

जब श्री सिंह ने कहा कि अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो अदालत को दखल देना चाहिए, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने पहले ही निर्देश दे दिया है कि वकीलों की गैर-मौजूदगी के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। इससे पहले दिन में, दिल्ली मेट्रो ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन समेत 16 स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की थी।

दिल्ली पुलिस ने एनएसए को लेकर फैली खबरों का किया खंडन, कहा-यह नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को लेकर सामने आई खबरों पर दिल्ली पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की है। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए उसे एनएसए के तहत कोई नई शक्ति नहीं दी गई है। यह आदेश वर्षों से लागू एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे हर तीन महीने में नवीनीकृत किया जाता है। दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने 15 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 की धारा 3(3) के तहत एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को एनएसए के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। इस अवधि के दौरान, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में आवश्यक समझा जाए, तो दिल्ली पुलिस आयुक्त एनएसए की धारा 3(2) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ निवारक हिरासत का आदेश जारी कर सकते हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया आदेश नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था लंबे समय से लागू है और इसे हर तीन महीने में नियमित रूप से बढ़ाया जाता है। दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयान में कहा गया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने यह खबर चलाई कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को एनएसए के तहत हिरासत की विशेष शक्तियां दी गई हैं।

तलवंडी राणा की तर्ज पर बदलेगी गांव गुंजार की श्मशान भूमि की तस्वीर

राह ग्रुप फाउंडेशन की मदद से तैयार हो रहा है आधुनिक श्मशान घाट का खाका

गुंजार की पांच सदस्यीय टीम ने किया तलवंडी राणा श्मशान घाट का दौरा

» हरियाणा, यूटर्न/ 23 जुलाई ।

हरियाणा में श्मशान घाटों को हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का केंद्र बनाने की दिशा में राह ग्रुप फाउंडेशन का अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अब गुंजार गांव की श्मशान भूमि को भी तलवंडी राणा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस उद्देश्य से गुंजार गांव की पांच सदस्यीय टीम ने रविवार एवं मंगलवार को तलवंडी राणा स्थित मॉडल श्मशान घाट का दौरा कर वहां किए गए विकास कार्यों का विस्तृत अवलोकन किया। दौरे के दौरान राह ग्रुप फाउंडेशन के चेयरमैन नरेश सेलपाड़, तलवंडी राणा श्मशान सुधार समिति के उपाध्यक्ष सारदूल वर्मा तथा संत फणीसानंद जी महाराज ने ठाकुर दास भार्गव स्कूल के अध्यापक मनोज यादव, आरपीएस महेंद्रगढ़ के प्रवक्ता अनिल कुमार, प्रदीप यादव सर्वोदय संस्थान, ब्लड बैंक, राजू नहरी विभाग तथा विभिन्न युवा क्लबों के पदाधिकारियों सहित पूरी टीम को तलवंडी राणा श्मशान घाट का भ्रमण करवाया और वहां अपनाई गई विभिन्न पर्यावरणीय एवं सौंदर्यीकरण तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्मशान केवल अंतिम संस्कार का स्थान नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण और सामाजिक प्रेरणा का केंद्र भी बन सकता है। राह संस्था के तकनीकि सहयोग से प्रस्तावित योजना के अनुसार गुंजार श्मशान घाट में एक आकर्षक पार्क, दो आधुनिक मॉर्निंग वॉक ट्रैक, दस प्रजातियों के छायादार एवं फलदार वृक्ष तथा आठ प्रकार के मौसमी फूलों का रोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त औषधीय पौधों की विशेष नर्सरी स्थापित करने, चार-लेयर वनस्पति प्रणाली विकसित करने तथा प्राकृतिक जैव विविधता को बढ़ावा देने की भी योजना बनाई गई है। गुंजार गांव का श्मशान घाट लगभग चार एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। हाल ही में यहां मिट्टी भराई का कार्य पूरा किया गया है, जिसके बाद इसे आधुनिक, स्वच्छ और हरित स्वरूप देने की योजना तैयार की जा रही है। राह ग्रुप फाउंडेशन के चेयरमैन नरेश सेलपाड़ ने बताया कि गुंजार की श्मशान भूमि के लिए अलग से विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि यह भी प्रदेश के आदर्श श्मशान घाटों में शामिल हो सके। निरीक्षण के दौरान टीम को मटका थैरेपी के माध्यम से जल संरक्षण, पौधों के बीच वैज्ञानिक दूरी बनाए रखने की तकनीक, वॉटर मैनेजमेंट, लैंडस्केपिंग, तालाब के उपचारित पानी से सिंचाई, पौध उत्पादन, फूलों की खेती तथा पर्यावरण अनुकूल हरित विकास मॉडल की विस्तृत जानकारी दी गई।

नीट पेपर लीक मामले में 'फास्ट-ट्रैकिंग' न्याय, चार राज्यों में स्थापित की जाएंगी अदालतें

नई दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द न्याय दिलाने और कड़ी सजा देने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों पर नए 'एंटी-चीटिंग' कानून के तहत कार्रवाई होगी और उन पर 'पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2024 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार चार राज्यों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत दोषी पाए जाने और सजा होने पर पांच साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। अभी हाईकोर्ट में लगभग चार मामले लंबित हैं और अब इन सभी मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार संबंधित राज्यों और हाईकोर्ट से इन मामलों के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का औपचारिक अनुरोध करने वाली है, ताकि रोजाना सुनवाई हो सके और मामलों का जल्द निपटारा हो सके।

चूंकि नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट) एक ऐसी परीक्षा है जिसे एनटीए आयोजित करती है। इसलिए इससे जुड़े पेपर लीक और अनुचित साधनों के मामले इस कानून के दायरे में आएंगे। सूत्रों ने बताया कि नीट लीक के संबंध में अब तक इस कानून के तहत चार एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन मामलों की सुनवाई के लिए बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर चार फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं। इनमें से दो मामले बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सूत्रों के मुताबिक, नए कानून में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ एनटीए द्वारा आयोजित सभी प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े अन्य पेपर लीक के मामले भी शामिल होंगे।

विपक्ष का उद्देश्य छात्र हितों की रक्षा नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ लेना है: शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई संसद के मानसून सत्र के दौरान नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बच रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए युवाओं की आकांक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर संसद में व्यापक चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष बार-बार अपना रुख बदल रहा है। पहले विपक्ष चर्चा की मांग करता है, फिर अलग नियम के तहत चर्चा की बात करता है और जब सरकार हर शर्त मानने को तैयार हो जाती है, तब भी विपक्ष चर्चा नहीं करता क्योंकि विपक्ष को यह डर है कि यदि सदन में बहस होगी तो उसके पुराने रिकॉर्ड और भूमिका पर भी सवाल उठेंगे।

ढोल बजाकर नगर परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल बंसल ने खोली जनस्वास्थ्य विभाग की पोल

हरियाणा, यूटर्न/ 23 जुलाई । हांसी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल बंसल ने गुरुवार को ढोल बजाकर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद द्वारा लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई सड़क को बिना पूर्व अनुमति तोड़ दिया गया और अब संबंधित विभाग एनओसी के नाम पर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा है। अनिल बंसल ने बताया कि दिल्ली गेट से राम मंदिर होते हुए जींद चौक तक बनी सड़क को पंचायती रामलीला ग्राउंड के सामने खोद दिया गया। उनका कहना है कि इस कार्य के लिए नगर परिषद से कोई अनुमति नहीं ली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क तोड़ने के बाद अब जनस्वास्थ्य विभाग उस बीएंडआर विभाग से एनओसी मांग रहा है, जिसका इस सड़क से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी सड़क को तोड़ने या पाइपलाइन बिछाने से पहले संबंधित विभाग से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में नियमों की अनदेखी की गई। साथ ही, इस संबंध में की गई शिकायत को भी बिना उचित जांच के बंद कर दिया गया। वाइस चेयरमैन ने कहा कि पिछले करीब 15 दिनों से सड़क टूटी हुई है, जिससे राहगीरों, व्यापारियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काठ मंडी के मुख्य मार्ग पर गड्ढों और मलबे के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है तथा दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई है।

दिल्ली पुलिस ने एनएसए को लेकर फैली खबरों का किया खंडन, कहा-यह नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को लेकर सामने आई खबरों पर दिल्ली पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की है। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए उसे एनएसए के तहत कोई नई शक्ति नहीं दी गई है। यह आदेश वर्षों से लागू एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे हर तीन महीने में नवीनीकृत किया जाता है।

दर असल, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने 15 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 की धारा 3(3) के तहत एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को एनएसए के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।

इस अवधि के दौरान, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में आवश्यक समझा जाए, तो दिल्ली पुलिस आयुक्त एनएसए की धारा 3(2) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ निवारक हिरासत का आदेश जारी कर सकते हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया आदेश नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था लंबे समय से लागू है और इसे हर तीन महीने में नियमित रूप से बढ़ाया जाता है।

दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयान में कहा गया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने यह खबर चलाई कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को एनएसए के तहत हिरासत की विशेष शक्तियां दी गई हैं।

पुलिस ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि मौजूदा नवीनीकरण का आदेश 7 जुलाई 2026 को जारी किया गया था, जो 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 की अवधि के लिए है।

फटाफट खबरें

शांतिपूर्ण संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करना सरासर गलत व निंदनीयः रामेश्वर पहलवान

» निर्मल सिंह विर्क

पानीपत, यूटर्न/ 23 जुलाई । जंतर-मंतर पर छात्रों के शांतिपूर्ण संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज व हिंसा की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए रामेश्वर पहलवान प्रदेश अध्यक्ष एस सी प्रकोष्ठ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जंतर-मंतर

छात्र नीट व अन्य परीक्षा के पेपर लीक को लेकर शांति पूर्वक संसद मार्च कर रहे थे। लेकिन उनकी आवाज को दबाने के पुलिस व फोर्स ने प्रदर्शन कर रहे बच्चों पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया, यहां तक कि छोटी छोटी बच्चियों पर भी लाठियां बरसाई। पुलिस व फोर्स के इस अनाचार के लिए इनेलो पार्टी कड़े शब्दों में निन्दा करती हैं। बच्चों पर बर्बरता पूर्वक लाठी बरसाने वाले घर जाकर कैसे अपने बच्चों से नजर मिलाएंगे। भाजपा सरकार ने छात्रों से बातचीत करने के बजाय तानाशाही रवैया अपनाते उन पर आंसू गैस के गोले बरसाएं,उन पर लठ बजवाई। उन्होंने मांग की तुरंत देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए, छात्रों पर लाठी चार्ज वह हिंसा की उच्च स्तरीय जांच की जाए, संसद मार्च के दौरान तमाम छात्रों और उनके समर्थन में आए लोगों को जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, परीक्षा लेने वाली प्राइवेट एजेंसी एनटीए को तुरंत भंग किया जाए। बच्चों के इस संघर्ष में इनेलो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ है।

नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान, हर संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की हो रही गहन जांच

नोएडा, यूटर्न/ 23 जुलाई । गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आने-जाने वाले प्रत्येक संदिग्ध वाहन और व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और कानून-व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे। यह अभियान डीसीपी नोएडा साद मियां खान एवं एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह के पर्यवेक्षण में संचालित किया जा रहा है। वहीं एसीपी-2 नोएडा मयंक तिवारी स्वयं थाना फेस-1 पुलिस टीम के साथ नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद रहकर चेकिंग अभियान की निगरानी कर रहे हैं।

ऑक्सफोर्ड स्कूल मतलोडा की छात्रा मंजू को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

» राजेश सलूजा

हरियाणा, यूटर्न/ 23 जुलाई । ऑक्सफोर्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मतलोडा की छात्रा मंजू ने एक बार फिर क्षेत्र का नाम पूरे हरियाणा में रोशन किया है। बारहवीं कक्षा (मार्च-2026) के परीक्षा परिणाम में विज्ञान संकाय में पूरे हरियाणा में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को रोहतक में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में मंजू को सम्मानित किया।

मंजू की इस उपलब्धि से विद्यालय, अभिभावकों और पूरे बरवाला क्षेत्र में खुशी का माहौल है। यह उपलब्धि छात्रा की कड़ी मेहनत,

अभिभावकों के सहयोग और विद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण का परिणाम मानी जा रही है।

विद्यालय के चेयरमैन प्रेमचंद शर्मा, निदेशक राजेन्द्र अत्री तथा उपनिदेशिका अनिता मलिक ने छात्रा मंजू, उसके माता-पिता और विद्यालय परिवार को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान पूरे विद्यालय के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि मंजू भविष्य में भी अपनी प्रतिभा के दम पर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी।

विद्यालय निदेशक राजेन्द्र अत्री ने बताया कि ऑक्सफोर्ड स्कूल लगातार उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। वर्ष 2019 में दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर विद्यालय को शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था। इसके बाद गत वर्ष दसवीं कक्षा में प्रथम एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले पांच-छह वर्षों से विद्यालय के विद्यार्थी लगातार हरियाणा की मेरिट सूची के टॉप-10 में स्थान बनाकर विद्यालय और क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहे हैं।

अत्री ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की लगन, अभिभावकों के विश्वास और शिक्षकों के समर्पण का सामूहिक परिणाम है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से इसी प्रकार मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का आ'ान करते हुए मंजू के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

प्रदेश सरकार द्वारा सडकों के निर्माण के लिए पारित किया जाएगा 99.16 लाख का बजट : सुभाष सुधा

» परमिंदर सिंह

कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 23 जुलाई । हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से सडकों के निर्माण के लिए 99.16 लाख रुपए का बजट पारित किया जाएगा है। इन सडकों के निर्माण की जिम्मेवारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। इन सडकों के निर्माण से शहर के लोगों को लाभ मिलेगा और सडकों से सम्बन्धित समस्याओं से निजात भी मिलेगी। पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा बुधवार को निवास कार्यालय पर कार्यकताओं से बातचीत करने उपरांत बोल रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही थानेसर हल्का का चहुंमुखी विकास कार्य 3 गुणा गति के साथ किया जा रहा है। इस हल्का में सडकों का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से शहर में सडक निर्माण को लेकर 99.16 लाख रुपए का बजट पारित किया जाएगा। इस कार्य को लोक निर्माण विभाग की तरफ से जल्द शुरू किया जाएगा और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष फोकस रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से गांधी नगर, नगर परिषद थानेसर में प्रताप के घर से बाईपास रोड तक आईपीबी सडक के निर्माण एवं पीवीसी पाइप बिछाने के कार्य पर 12.57 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। गांधी नगर, नगर परिषद थानेसर में लाडेन के घर से बिशु के घर तक, सुमन देवी के घर से रोशन के घर तक, शेर सिंह के घर से सतपाल के घर तक तथा पीडब्ल्यूडी मुख्य सडक से नरेंद्र के घर तक आईपीबी सडकों के निर्माण कार्य पर 29.61 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। इसके अलावा गांधी नगर, नगर परिषद थानेसर में राजिंदर के घर से डेविड के घर तक, राजिंदर पंडित के घर से करण चावला के घर तक, मीना के घर से हनुमान मंदिर तक तथा राजा राम के घर से बलराज के घर तक आईपीबी सडकों के निर्माण कार्य पर 32.66 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने कहा कि वार्ड नं. 3 नगर परिषद थानेसर में 24.32 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक (आईपीबी) सडकों का निर्माण कार्य किया जाएगा।

दूसरे दिन भी जारी रहा पटरी मरम्मत का काम, क्रॉस ओवर अब भी क्षतिग्रस्त

» साहिबाबाद, यूटर्न/ 23 जुलाई

गाजियाबाद-नई दिल्ली रेलखंड पर सोमवार देर रात मालगाड़ी के डिब्बे पलटने से क्षतिग्रस्त हुए रेलवे ट्रैक की मरम्मत बुधवार को भी जारी रही। हादसे के 20 घंटे बाद रेलवे कर्मियों ने क्षतिग्रस्त ट्रैक को 90 फीसदी तक दुरुस्त कर लिया है। ट्रैक से कोयला भी हटवाने काम भी काफी हद तक पूरा हो गया है। बुधवार को रेलवे ट्रैक के बीच पड़े क्षतिग्रस्त स्लैब (स्लीपर) को ठीक किया गया। हालांकि हादसे के दूसरे दिन भी क्रॉस ओवर (हाइटेंशन लाइन) बुधवार शाम तक दुरुस्त नहीं हो सका। अधिकारियों ने 48 घंटे में यातायात को सुचारू करने का दावा किया है। नॉर्दन रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि मालगाड़ी सोनभद्र जिले के शक्तिनगर से हरियाणा में हिसार जिले के खेदड़ गांव स्थित राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन पर जा रही थी।

प्रदेश सरकार द्वारा सडकों के निर्माण के लिए पारित किया जाएगा 99.16 लाख का बजटः सुभाष सुधा

थानेसर के लोगों को सडकों से सम्बन्धित समस्याओं से मिलेगी निजात

» अश्विनी वालिया

कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 23 जुलाई । हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से सडकों के निर्माण के लिए 99.16 लाख रुपए का बजट पारित किया जाएगा है। इन सडकों के निर्माण की जिम्मेवारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। इन सडकों के निर्माण से शहर के लोगों को लाभ मिलेगा और सडकों से सम्बन्धित समस्याओं से निजात भी मिलेगी।

पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा बुधवार को निवास कार्यालय पर कार्यकताओं से बातचीत करने उपरांत बोल रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही थानेसर हल्का का चहुंमुखी विकास कार्य 3 गुणा गति के साथ किया जा रहा है। इस हल्का में सडकों का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से शहर में सडक निर्माण को लेकर 99.16 लाख रुपए का बजट पारित किया जाएगा। इस कार्य को लोक निर्माण विभाग की

तरफ से जल्द शुरू किया जाएगा और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष फोकस रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से गांधी नगर, नगर परिषद थानेसर में प्रताप के घर से बाईपास रोड तक आईपीबी सडक के निर्माण एवं पीवीसी पाइप बिछाने के कार्य पर 12.57 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। गांधी नगर, नगर परिषद थानेसर में लाडेन के घर से बिशु के घर तक, सुमन देवी के घर से रोशन के घर तक, शेर सिंह के घर से सतपाल के घर तक तथा पीडब्ल्यूडी मुख्य सडक से नरेंद्र के घर तक आईपीबी सडकों के निर्माण कार्य पर 29.61 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। इसके अलावा गांधी नगर, नगर परिषद थानेसर में राजिंदर के घर से डेविड के घर तक, राजिंदर पंडित के घर से करण चावला के घर तक, मीना के घर से हनुमान मंदिर तक तथा राजा राम के घर से बलराज के घर तक आईपीबी सडकों के निर्माण कार्य पर 32.66 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

उन्होंने कहा कि वार्ड नं. 3 नगर परिषद थानेसर में 24.32 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक (आईपीबी) सडकों का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके अलावा वेदपाल के घर से जसवीर के घर तक, राजू रंगा के घर होते हुए। झांसा रोड से सुरेंद्र के घर तक, मेवा राम के घर से सतीश के घर तक, कालीराम के घर से गुलशन किरयाना स्टोर तक सडक निर्माण कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से थानेसर हल्का के विकास का सैंकडों करोड का बजट खर्च किया जा चुका है। इस सरकार ने गांव और शहरों के हर वार्ड का सामान रूप से विकास कार्य करवाया है। इस सरकार ने सबका साथ सबका विकास की नीति को आधार मानकर विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने का काम किया है।

इस्कॉन की भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा आज, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र नगरी सजकर तैयार

क्रेन के माध्यम से अर्पित होगा 56 भोग

» अश्विनी वालिया

कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 23 जुलाई । धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज 24 जुलाई को इस्कॉन द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी की भव्य वार्षिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। पुरी की विश्वप्रसिद्ध रथ यात्रा की तर्ज पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। हरिनाम संकीर्तन, पुष्पवर्षा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं विशाल भंडारे के साथ यह उत्सव पूरे नगर को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर देगा। इस्कॉन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान साक्षी गोपाल प्रभुजी ने बताया कि रथ यात्रा का शुभारंभ ज्योतिसर स्थित श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में भगवान की विशेष पूजा-अर्चना एवं महाआरती के साथ होगा। इसके पश्चात भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी का भव्य रथ नगर भ्रमण के लिए निकलेगा। श्रद्धालु भगवान के रथ की रस्सी खींचकर उनके दिव्य दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे।

कार्यक्रम की रूपरेखा

रथ यात्रा महोत्सव के अंतर्गत प्रातःकाल से ही श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर, ज्योतिसर में विशेष पूजा-अर्चना एवं दर्शन का क्रम प्रारंभ होगा।

दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी की विशेष महाआरती, कीर्तन एवं महाप्रसाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सायंकाल 5 बजे श्री व्यास गौड़ीय मठ, ब्रह्मसरोवर से भगवान का भव्य रथ नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान करेगा। रथ यात्रा ब्रह्मसरोवर, जाट धर्मशाला, थीम पार्क, गुरुद्वारा चौक, रेलवे रोड, खंडा चौक होते हुए सेक्टर-13 स्थित कम्युनिटी सेंटर पहुंचेगी, जहां विशाल भंडारे एवं महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।

यात्रा मार्ग पर विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा भगवान का स्वागत किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद, शीतल पेय एवं अन्य सेवा व्यवस्थाएं भी की गई हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को विशेष रूप से 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए यह विशेष आकर्षण का केंद्र होगा, जब क्रेन की सहायता से ऊंचाई पर विराजमान भगवान को भव्य छप्पन भोग समर्पित किया जाएगा। इस दौरान हरिनाम संकीर्तन एवं जयघोषों से पूरा वातावरण गुंजायमान रहेगा।

हरिनाम संकीर्तन, पुष्पवर्षा और स्वागत मंच रहेंगे आकर्षण

रथ यात्रा मार्ग पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों द्वारा स्वागत मंच लगाए जाएंगे। अनेक स्थानों पर भगवान के रथ पर पुष्पवर्षा की जाएगी तथा श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेय एवं प्रसाद वितरण की व्यवस्था रहेगी। यात्रा में इस्कॉन के भक्त मधुर हरिनाम संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे संपूर्ण नगर में आध्यात्मिक उत्साह का वातावरण बनेगा।

यूटर्न टाइम
THE GOOD, BAD & UGLY OF INDIA

पहले नैरेटिव खत्म करो, फिर विरोध

संदीप शर्मा

एक समय था जब सरकारें विरोध प्रदर्शनों को तितर-बितर कर देती थीं। अब वे पहले उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती हैं। अगर जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (उखढ) के विरोध प्रदर्शन की घटनाओं को देखें, तो लड़ाई अब सड़कों और बैरिकेड्स की नहीं रही। यह लड़ाई अब लोगों की सोच या 'परसेप्शन' की है। एक विरोध प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण होने का दावा करता है, अचानक खुद को ट्रकों में भरे पत्थरों, टीवी स्क्रीन पर दिख रही क्षतिग्रस्त गाड़ियों और वर्दीधारी पुलिसकर्मियों के साथ सादे कपड़ों में लाठी लिए लोगों से घिरा हुआ पाता है। साफ सवाल यह है: यह पटकथा कौन लिख रहा है? एक और बात भी हैरान करने वाली है। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिखे कई पुलिसकर्मियों के पास कथित तौर पर कोई पहचान-पत्र (बैज) नहीं था। क्यों? अगर पुलिस सिर्फ.कानून लागू कर रही है, तो किसी को अपनी पहचान बताने वाला बैज पहनने में हिचकिचाहट क्यों होनी चाहिए? बैज जनता की सुरक्षा करता है। यह ईमानदार पुलिस अधिकारियों को झूठे आरोपों से भी बचाता है। सिवाय इसके कि पहचान छिपाना अचानक वर्दी का हिस्सा बन गया हो। फिर सादे कपड़ों में लाठी लिए वे लोग भी हैं।

वे असल में कौन हैं? पुलिस? वॉलंटीयर्स? उस दिन के 'शो' के लिए हायर किए गए एक्स्ट्रा कलाकार? जब कोई नागरिक अधिकृत पुलिस अधिकारी और लाठी लिए अनजान व्यक्ति के बीच फर्क नहीं कर पाता, तो लोकतंत्र खतरनाक स्थिति में पहुँच जाता है।

और वे पत्थर। कितनी कमाल की टाइमिंग है। ठीक उसी समय जब देश हाल के वर्षों के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक को देख रहा है, ट्रकों में भरे पत्थर आसानी से सीन में आ जाते हैं।

लगभग उम्मीद होती है कि अगले सीन में एक वॉइस-ओवर सुनाई देगा: 'किसी भी स्वाभाविक घटना से समानता पूरी तरह से संयोग है।' क्षतिग्रस्त गाड़ियों का भी खास ज़िक्र होना चाहिए। वे इतनी पाबंदी से सामने आती हैं कि सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। हर शाम, वे दर्शकों को पूरी ईमानदारी से याद दिलाती हैं कि प्रदर्शनकारी हिंसक रहे होंगे।

जांच? सबूत? वे इंतजार कर सकते हैं। विजुअल्स ने पहले ही फैसला सुना दिया है। फिर भी टीवी फ्रेम के बाहर, एक और भारत चुपचाप बोल रहा है और कॉकरोचों के समर्थन में खड़ा है।

देश के हर कोने से लोग स्विगी और जोमैटो के जरिए उखढ प्रदर्शनकारियों के लिए खाना ऑर्डर कर रहे हैं। कोई भारत के किसी कोने से लंच के पैसे दे रहा है। कोई चाय ऑर्डर कर रहा है। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिनर ऑर्डर करता है। भारत के किसी हिस्से से एक रिटायर्ड टीचर पानी की बोतलों का खर्च उठाता है। लोग ऐसे आंदोलन पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते जिसे वे हिंसक मानते हों। वे ऐसे आंदोलन पर ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जिसे वे समर्थन के लायक समझते हैं। शायद यही बात कुछ लोगों को परेशान कर रही है। क्योंकि जब पूरी तरह अनजान लोग प्रदर्शनकारियों को खाना खिला रहे हों, तो उन्हें विलेन के तौर पर दिखाना मुश्किल होता है। यह अंतर बहुत साफ है। एक तरफ, देश को पत्थर, टूटी हुई गाड़ियाँ और कथित अव्यवस्था की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। दूसरी तरफ, आम नागरिक फूड डिलीवरी ऐप खोलकर अपने पैसे खर्च करते हैं ताकि प्रदर्शनकारी—जिनसे वे कभी नहीं मिले—भूखे न रहें। एक नैरेटिव खतरे की बात करता है; दूसरा एकजुटता की। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकतीं। इतिहास गवाह है कि सरकारें शायद ही कभी जनता की राय को गढ़ने की कोशिश करके जीतती हैं। वे मुश्किल सवालों के जवाब देकर जीतती हैं। अगर किसी आंदोलन में कमियाँ हैं, तो उन्हें तथ्यों के साथ सामने लाएँ। अगर प्रदर्शनकारियों ने कानून तोड़ा है, तो सबूतों के साथ उन पर मुकदमा चलाएँ। लेकिन अगर रणनीति यह है कि तथ्यों के सामने आने से पहले ही ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें हर प्रदर्शनकारी दोषी दिखे, तो इससे न सिर्फ.एक आंदोलन कमजोर होता है, बल्कि संस्थाओं में जनता का भरोसा भी कमजोर होता है। किसी आंदोलन को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका है उसके सवालों का जवाब न देना। तरीका है—मुद्दा बदल देना। मांगों के बजाय पत्थरों की बात करना। टूटे वादों के बजाय टूटे शीशों की बात करना। नुकसान पहुँची संस्थाओं के बजाय नुकसान पहुँची गाड़ियों की बात करना। हो सकता है कल और भी नाटकीय तस्वीरें सामने आएँ। शायद पत्थरों से भरा एक और ट्रक। शायद एक और टूटी हुई विंडस्क्रीन। शायद लाठियों के साथ कुछ और अनजान लोग। लेकिन एक सवाल बना रहेगा। अगर आंदोलन सचमुच हिंसक है, तो सबूतों को सामने आने दें। अगर यह सचमुच शांतिपूर्ण है, तो वह भी दिखना चाहिए। लोकतंत्र में, सरकारों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद की जाती है—न कि दिखावा करने की। क्योंकि जब कहानी से ज्यादा स्क्रिप्ट अहम हो जाती है, तो दर्शक आखिरकार डायरेक्टर पर भरोसा करना छोड़ देते हैं।

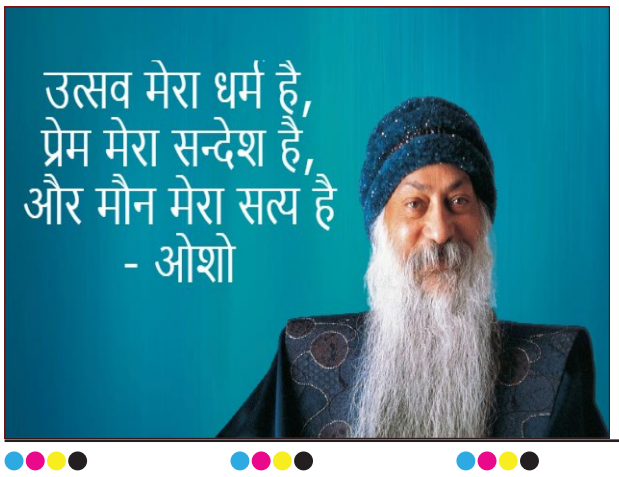

सिक्किम हादसा: प्रकृति की चेतावनी या मानवीय लापरवाही?

सुनील कुमार महला

ताजा उपलब्ध जानकारी के अनुसार(यह आलेख लिखे जाने तक) 20 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं तथा 2 लोग सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे तथा रिपोर्ट के समय तक 5 लोगों की तलाश जारी थी। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि सुरंग में प्राकृतिक रूप से जमा मीथेन गैस को निकालने के प्रयास के दौरान विस्फोट/दहन हुआ, जिससे भूस्खलन हुआ और सुरंग का प्रवेश मार्ग बंद हो गया। हालांकि, अंतिम कारण विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

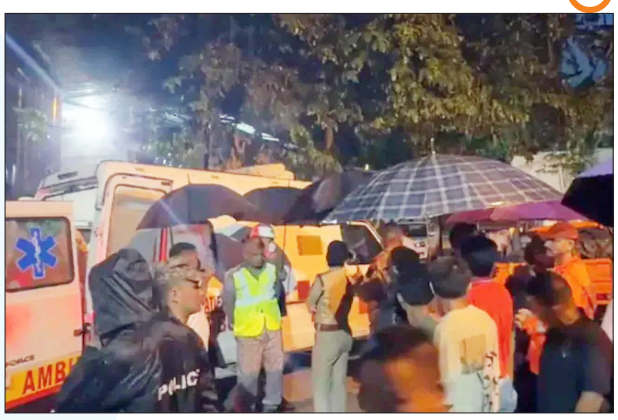

हाल ही में सिक्किम के समरडुंग, नामची जिले में एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज-श्क जलविद्युत परियोजना के निमार्णाधीन टनल (एडीआइटी-3) में हादसा हो गया। मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 20 जुलाई 2026 को निमार्णाधीन सुरंग के अंदर अचानक मीथेन गैस से जुड़ी घटना (संभावित विस्फोट/दहन) हुई और इसके बाद सुरंग के प्रवेश मार्ग के पास भूस्खलन हुआ, जिससे सुरंग का हिस्सा बंद हो गया और अंदर मौजूद कर्मचारी व अधिकारी फंस गए। बताया जा रहा है कि सुरंग में 40 से अधिक लोग मौजूद थे। इनमें से कुछ लोग समय रहते बाहर निकल आए, लेकिन लगभग 25-27 लोग अंदर फंस गए। जानकारी अनुसार इनमें एनएचपीसी, ठेकेदार कंपनी और मजदूर शामिल थे। ताजा उपलब्ध जानकारी के अनुसार(यह आलेख लिखे जाने तक) 20 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं तथा 2 लोग सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे तथा रिपोर्ट के समय तक 5 लोगों की तलाश जारी थी। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि सुरंग में प्राकृतिक रूप से जमा मीथेन गैस को निकालने के प्रयास के दौरान विस्फोट/दहन हुआ, जिससे भूस्खलन हुआ और सुरंग का प्रवेश मार्ग बंद हो गया। हालांकि, अंतिम कारण विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। राहत एवं बचाव कार्य में राज्य पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, दमकल तथा अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों को लगाया गया। इधर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने भी घटनास्थल का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की है। बहरहाल, यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि भूस्खलन के कारण इस सुरंग के ढह जाने से कई लोगों की मौत हो जाने की घटना ने पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहाड़ों की पारिस्थितिकी की अनदेखी कर विकास कितना नुकसानदेह हो सकता है, यह अब कोई छिपी बात नहीं है। हाल फिलहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि हमारे देश में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) एक गंभीर प्राकृतिक आपदा बनता जा रहा है। मानसून के दौरान हिमालयी और पश्चिमी घाट के राज्यों में इसकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल के दिनों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा के कारण कई बड़े भूस्खलन हुए हैं। वास्तव में,अत्यधिक वर्षा और बादल फटना, भारत के हिमालयी क्षेत्र का भूकंपीय दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय होना, अनियोजित विकास (पेड़ों की अंधाधुंध कटाई,सड़क, सुरंग, जलविद्युत परियोजनाओं और भवन निर्माण के दौरान वैज्ञानिक मानकों की अनदेखी), विकास के नाम पर पहाड़ों का काटा जाना, जलवायु परिवर्तन (अत्यधिक और अल्प अवधि की वर्षा) भूस्खलन के प्रमुख कारणों में से एक हैं तथा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) तथा पश्चिमी घाट (केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र) हमारे देश में सबसे अधिक भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में से एक हैं। गौरतलब है कि भारत का लगभग 12.6% भौगोलिक क्षेत्र भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्र में आता है तथा इस क्रम में इसरो (राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र) ने वर्ष 1998झ2022 के दौरान भारत में लगभग 80,000 भूस्खलनों का डेटाबेस तैयार किया है। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ,इसरो का एक प्रमुख केंद्र है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। बहरहाल, भूस्खलन का यह हमारे देश में पहला हादसा नहीं है। उत्तराखंड और तेलंगाना में भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन उनसे कोई सबक नहीं लिया गया। कहना गलत नहीं होगा कि हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में यदि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया, तो यह गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। सवाल यह भी उठता है कि बरसात के मौसम में सुरंग निर्माण का काम करते समय आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए गए? इस दुर्घटना में जिन श्रमिकों की जान गई, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या परियोजना से जुड़े अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी?

छात्र आंदोलन: मुद्दों से भटकती बहस और भविष्य की चिंता

डॉ. सत्यवान सौरभ

लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन केवल अधिकार नहीं, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम भी है। जब व्यवस्था में कोई गंभीर खामी सामने आती है, तब जनता अपनी आवाज बुलंद करती है और सरकार से जवाब मांगती है। विशेष रूप से जब मामला लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा हो, तब विरोध का स्वर और अधिक स्वाभाविक हो जाता है। नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की खबरों ने पूरे देश के युवाओं और उनके अभिभावकों को चिंतित किया। वर्षों की कठिन मेहनत के बाद यदि किसी परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग जाए, तो आक्रोश पैदा होना असामान्य नहीं है। किंतु इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा किया कि क्या छात्र आंदोलनों का उद्देश्य वास्तव में छात्रों का भविष्य रह गया है, या फिर वे धीरे-धीरे राजनीतिक और वैचारिक संघर्षों का मंच बनते जा रहे हैं?

किसी भी छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी नैतिकता होती है। जब छात्र अपने अधिकारों और भविष्य के लिए संघर्ष करते हैं, तब समाज उनके साथ खड़ा होता है। अभिभावक, शिक्षक और आम नागरिक भी उनकी मांगों को उचित मानते हैं। लेकिन जैसे ही आंदोलन का केंद्र बदलने लगता है और मूल मुद्दे से असंबंधित विषय मंच पर आने लगते हैं, तब उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। यदि परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध का मंच ऐसे नारों, भाषणों या विवादों का केंद्र बन जाए जिनका शिक्षा व्यवस्था से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, तो आंदोलन की गंभीरता कम होती है और वास्तविक मुद्दा पीछे छूट जाता है। आज देश का युवा पेपर लीक से परेशान है। उसे इस बात की चिंता है कि वर्षों की मेहनत कहीं किसी अपराधी गिरोह की वजह से व्यर्थ न चली जाए। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह होना चाहिए कि पेपर लीक कैसे रुकेंगे, परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित कैसे बनाया जाएगा, दोषियों को कितनी जल्दी और कितनी कठोर सजा मिलेगी तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-से संस्थागत सुधार किए जाएंगे। यदि इन मूल प्रश्नों के स्थान पर केवल राजनीतिक नारे और सरकार विरोध या सरकार समर्थन की बहस प्रमुख हो जाए, तो समाधान की दिशा कमजोर पड़ जाती है।

यह भी स्वीकार करना होगा कि पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है। अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग सरकारों के समय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले सामने आते रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि समस्या किसी एक दल, एक मंत्री या एक सरकार तक सीमित नहीं है। समस्या उस तंत्र में है जिसमें अपराधी गिरोह सेंध लगाने में सफल हो जाते हैं। इसलिए यदि हर बार केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक ही चर्चा सीमित रहेगी, तो वास्तविक अपराधी बच निकलेंगे और विद्यार्थी बार-बार पीड़ित होंगे। किसी मंत्री का इस्तीफा लोकतांत्रिक जवाबदेही का विषय हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में अंतिम समाधान नहीं है। मंत्री बदलने से व्यवस्था तभी बदलेगी जब प्रशासनिक सुधार, तकनीकी सुरक्षा, पारदर्शी जांच और कठोर दंड व्यवस्था लागू होगी। यदि जड़ पर प्रहार नहीं होगा तो केवल चेहरे बदलने से परिणाम नहीं बदलेंगे। इसलिए छात्र आंदोलनों का केंद्र व्यक्ति नहीं, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए।

सोशल मीडिया के दौर में आंदोलनों की दिशा बहुत तेजी से बदलती है। कुछ सेकंड की वीडियो क्लिप, एक नारा या एक पोस्ट पूरे आंदोलन की छवि तय कर देती है। यही कारण है कि आंदोलन से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। यदि मंच पर ऐसे नारे सुनाई दें जिनका परीक्षा या शिक्षा से कोई संबंध न हो, तो आम नागरिक यह सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या आंदोलन का मूल उद्देश्य वही है जो शुरूआत में बताया गया था। लोकतंत्र में विचारधाराओं का स्थान है, लेकिन जब छात्र आंदोलन वैचारिक प्रतिस्पर्धा का माध्यम बन जाए, तब सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं छात्रों का होता है जिनके नाम पर आंदोलन शुरू हुआ था।

रुपया पांच पैसे मजबूत होकर 96.48 प्रति डॉलर पर खुला

मुंबई, यूटर्न/ 23 जुलाई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संभावित हस्तक्षेप के बीच रुपया गुरुवार को शुरूआती कारोबार में पांच पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.48 पर पहुंच गया।हालांकि, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से घरेलू मुद्रा पर दबाव कायम है।विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी पूंजी की निकासी और घरेलू शेयर बाजारों में लगातार कमजोर धारणा से भी रुपये पर दबाव बना रहा।हालांकि, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी से स्थानीय मुद्रा को कुछ राहत मिली।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 96.53 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में बढ़कर 96.48 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से पांच पैसे की बढ़त दर्शाता है।रुपया बुधवार को 28 पैसे की गिरावट के साथ 96.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 100.97 पर रहा।

रुपए को स्थिर रखने के लिए आरबीआई ने बेचे अरबों डॉलर

नई दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई महीने में विदेशी मुद्रा हाजिर बाजार में 6 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की है। यह कदम कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण रुपये में आने वाली अस्थिरता को रोकने और उसे स्थिर बनाए रखने के लिए उठाया गया। आरबीआई के इस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, मई में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में मात्र 0.1 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई, जो केंद्रीय बैंक के प्रयासों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मई में आरबीआई ने कुल 22.2 अरब डॉलर बेचे, जबकि 16.2 अरब डॉलर खरीदे, जिससे शुद्ध बिक्री 6 अरब डॉलर रही। इससे पहले, अप्रैल में भी रिजर्व बैंक ने 8.95 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की थी। फॉरवर्ड बाजार में भी, मई के अंत तक आउटस्टैंडिंग नेट शॉर्ट डॉलर पोजीशन अप्रैल के 95.3 अरब डॉलर से बढ़कर 106.7 अरब डॉलर हो गई है, जो रुपये के प्रबंधन में आरबीआई की बहुआयामी रणनीति को उजागर करता है।

चालू माह में तीन और दमदार गाड़ियां लांच की तैयारी

नई दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई । चालू महीने के अगले दो हफ्तों में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार तीन और दमदार गाड़ियां भारत में अपनी जगह बनाने को तैयार हैं। सबसे पहले, मारुति सुजुकी अपनी लोकप्रिय सब-4 मीटर एसयूवी ब्रेजा का फेसलिफ्ट वर्जन 23 जुलाई को लॉन्च करेगी। इस नए मॉडल में स्पोर्टी लाल एक्सेंट वाली नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और सिल्वर स्किड प्लेट जैसे बाहरी बदलाव दिखेंगे। केबिन में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल क्लस्टर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें होंगी। इंजन विकल्पों में मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल और सीएनजी के साथ-साथ फ्रोंक्स का 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिलेगा। सीएनजी वेरिएंट में अंडरबॉडी टैंक बूट स्पेस को बढ़ाएगा। इसके बाद, टोयोटा अपनी नई जनरेशन हिल्क्स पिक-अप ट्रक को 28 जुलाई, 2026 को बाजार में उतारेगी। इसमें माइल्ड हाइब्रिड (एमएचईवी) तकनीक के साथ 48वी सिस्टम और एक शक्तिशाली 2.8-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन होगा, जो 201बीएचपी की पावर और 500एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। नया फ्रंट लुक और मस्कुलर एक्सटीरियर डिजाइन इसे मौजूदा मॉडल से अलग बनाएगा। होंडा अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी जेडआर-वी हाइब्रिड की कीमतों का खुलासा 20 से 21 जुलाई के बीच करने वाली है। यह प्रीमियम एसयूवी 2.0-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन पेट्रोल इंजन के साथ होंडा के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम से लैस है, जो 184बीएचपी की पावर और 22.80 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज देता है।

देश भर में जारी हुए 77 लाख से अधिक वार्षिक फास्टैग पास

नेशनल हाईवे पर दर्ज हुए 63 करोड़ ट्रांजैक्शन्स : सरकार

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई ।**

देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है।केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि जून 2026 तक 77 लाख से अधिक वार्षिक फास्टैग पास जारी किए जा चुके हैं।

इन पासों के माध्यम से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर 63 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि वर्तमान में कार, जीप और वैन श्रेणी के वाहनों द्वारा किए जाने वाले कुल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) लेनदेन में लगभग 33 प्रतिशत हिस्सेदारी वार्षिक फास्टैग पास की है।उन्होंने कहा कि इस योजना से टोल संचालन अधिक कुशल हुआ है और सड़क उपयोगकताओं की यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक बनी है। मंत्री ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने टोल शुल्क से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए कई शिकायत निवारण व्यवस्थाएं विकसित की हैं। इसके अलावा टोल शुल्क संग्रह में पारदर्शिता और संचालन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने फास्टैग-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू किया है। सरकार के अनुसार, वर्तमान में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) कार्यक्रम के तहत नेशनल हाईवे पर होने वाले कुल टोल शुल्क संग्रह का करीब 98 प्रतिशत फास्टैग के माध्यम से किया जा रहा है।

सरकार ने बताया कि सभी फास्टैग लेनदेन एक सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था के तहत पूरे किए जाते हैं, जिसमें टोल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, टोल प्लाजा का अक्वायरर बैंक, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) केंद्रीय क्लियरिंग हाउस के रूप में तथा फास्टैग जारी करने वाला बैंक शामिल होता है।

दोहरे सीएनजी सिलेंडर वाली कारों ने मचाई धूम

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई ।**

दोहरे सीएनजी सिलेंडर वाली कारों ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में धूम मचा दी है। यह कारें पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में करीब 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज देती हैं। इन कारों की विशेषता ग्राहकों को ईंधन पर भारी बचत प्रदान करती है। इन कारों की शुरूआती कीमत 5.53 लाख रुपये से है और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दो सीएनजी सिलेंडर होने के बावजूद इनमें पूरा बूट स्पेस मिलता है, जिससे व्यावहारिक उपयोगिता बढ़ जाती है। आइए जानते हैं भारतीय बाजार में उपलब्ध ऐसी ही 7 कारों के बारे में। रुपए 5,79,990 की शुरूआती कीमत वाली टाटा टियागो सीएनजी कार में 1.2-लीटर इनलाइन थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध है।

बीएसई ने लॉन्च किया 'टोटल मार्केट इंडेक्स', अब व्यापक बाजार को ट्रैक करना होगा आसान

» **मुंबई, यूटर्न/ 23 जुलाई ।**

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने गुरुवार को नए बेंचमार्क बीएसई टोटल मार्केट इंडेक्स (टीएमआई) को लॉन्च किया है। यह बाजार पूंजीकरण के हिसाब से बीएसई ऑलकैप में मौजूद 98 प्रतिशत कंपनियों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके जरिए एक्सचेंज की कोशिश बाजार की ट्रैकिंग को आसान बनाना है। एक्सचेंज के अनुसार, यह इंडेक्स बीएसई ऑलकैप यूनिवर्स के कम से कम 98 प्रतिशत हिस्से को कवर करेगा (जिसमें कम से कम 1,000 स्टॉक्स शामिल होंगे), जिससे यह भारतीय इक्विटी मार्केट के लिए सबसे व्यापक बेंचमार्क में से एक बन जाएगा।

बीएसई टोटल मार्केट इंडेक्स की बेस वैल्यू 1,000 है और इसकी पहली वैल्यू डेट 16 सितंबर, 2005 है। इस इंडेक्स को हर छह महीने में (जून और दिसंबर) पुनर्गठित किया जाएगा।

इस इंडेक्स का संचालन बीएसई की सहयोगी कंपनी बीएसई इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया जाएगा, जो अन्य इंडेक्स का भी संचालन करती है।

बीएसई इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशुतोष सिंह ने कहा कि इस इंडेक्स को भविष्य के हिसाब से तैयार किया गया है। यह भारत के कैपिटल मार्केट की ग्रोथ के साथ-साथ बढ़ता है, न कि कुछ तय कंपनियों या शेयरों तक ही सीमित रहता है। उन्होंने कहा, 'बीएसई टोटल मार्केट इंडेक्स को इस तरह से बनाया गया है कि जैसे-जैसे भारत का कैपिटल मार्केट बढ़ेगा, यह भी बढ़ेगा। यह लिस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के दायरे का व्यापक और सही प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही यह भी दिखाता है कि मार्केट में कैसे बदलाव आ रहे हैं।'

होंडा जल्द ही नई फ्लैगशिप एसयूवी जेडआर-वी हाइब्रिड करेगी लांच

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई**

जल्द ही होंडा भारतीय बाजार में अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी, जेडआर-वी हाइब्रिड, लॉन्च करने वाली है। यह लग्जरी एसयूवी होंडा को एक नए और महंगे सेगमेंट में स्थापित करेगी। जुलाई 2026 में इसकी कीमतों की घोषणा की जाएगी। इसी महीने से डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी, जिसकी बुकिंग मई 2026 से जारी है। यह एसयूवी सीबीयू रूट के माध्यम से विदेश से आयात की जाएगी, जिससे इसकी सीमित उपलब्धता होगी। भारतीय मार्केट में इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 40 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

इसका सीधा मुकाबला फॉक्सवैगन टिगुआन, स्कोडा कोडियाक और जीप मेरिडियन जैसी प्रीमियम एसयूवी से होगा। जेडआर-वी हाइब्रिड में 2.0-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ डुअल-मोटर हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जो कुल 184बीएचपी की पावर और 315 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। होंडा का दावा है कि यह एसयूवी मात्र 8 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और 22.80 किमी/लीटर का बेहतरीन माइलेज देगी। इसकी टॉप स्पीड 172 किमी/घंटा है। इसके मॉडर्न केबिन में 9-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले (वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ) और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। अन्य प्रीमियम फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड फ्रंट सीट्स और 12-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 8-एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल-2 अडास जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं।

जल्द आ रहीं है कई 7-सीटर इलेक्ट्रिक कारें एवं एसयूवी

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 23 जुलाई ।**

भारत में कई प्रमुख वाहन निमार्ता कंपनियां जल्द ही बैटरी से चलने वाली शानदार 7-सीटर कारें और एसयूवी पेश करने की तैयारी में हैं। इनमें सबसे पहले मारुति सुजुकी अपनी पहली 3-रो इलेक्ट्रिक एमपीवी वायएमसी को 2026 के अंत तक दुनिया के सामने पेश कर सकती है, जिसकी बिक्री 2027 में शुरू होगी।

यह हरटेक्ट-ई प्लेटफॉर्म पर बनेगी और 49 केडब्ल्यूएच व 61 केडब्ल्यूएच बैटरी विकल्पों के साथ करीब 500 किलोमीटर की रेंज देगी। मारुति की पार्टनरशिप के तहत, टोयोटा भी इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी एक इलेक्ट्रिक एमपीवी लाएगी, जिसका बाहरी डिजाइन अलग होगा लेकिन रेंज और बैटरी पैक समान रहेंगे। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया इस साल त्योहारी सीजन के आसपास अपनी नई हेक्टर हॉक ईवी का फुल-इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करेगी। यह एडीएपीटी प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसमें 56.7 केडब्ल्यूएच का बैटरी पैक 450 से 500 किलोमीटर की रियल-वर्ल्ड रेंज दे सकता है। टाटा मोटर्स भी अपनी सबसे प्रीमियम एसयूवी सफारी ईवी की भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग शुरू कर चुकी है, जिसके त्योहारी सीजन तक लॉन्च होने की उम्मीद है।

यह कंपनी के नए एक्टी.ईवी प्लस प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और 65 केडब्ल्यूएच या 75 केडब्ल्यूएच के बड़े बैटरी पैक के साथ 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज दे सकती है। इसके अतिरिक्त, टाटा मोटर्स अपने लग्जरी इलेक्ट्रिक ब्रांड अविन्या के तहत एक बड़ी तीन-कतारों वाली प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी तैयार कर रही है, जिसके 2027 तक मार्केट में आने की उम्मीद है।

यह चेरी-जेएलआर के फ्रीलैंडर ईवी प्लेटफॉर्म पर बनेगी और इसमें 65 केडब्ल्यूएच से 80 केडब्ल्यूएच क्षमता वाले बेहद पावरफुल बैटरी पैक मिल सकते हैं। ये आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर होंगी, बल्कि इनमें कमाल के फीचर्स और तगड़ी ड्राइविंग रेंज भी मिलेगी।

फटाफट खबरें

दिल्ली जाने वाले रास्तों पर बढ़ाई गई सुरक्षा

फरीदाबाद, यूटर्न/ 23 जुलाई । दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी। दिल्ली से सटे जिले के प्रमुख रास्तों और प्रवेश मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। पुलिस ने कई स्थानों पर नाकाबंदी कर दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों की जांच की और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। सुबह से ही पुलिस की अलग-अलग टीमें दिल्ली से जुड़े मार्गों पर सक्रिय रहीं। कार, बस, ट्रैक्टर-ट्रॉली, कंटेनर और अन्य वाहनों को रोककर जांच की गई। वाहन चालकों से उनके सफर का कारण, जाने वाले स्थान और पहचान संबंधी जानकारी ली गई। जिन वाहनों पर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों या अन्य समूहों के झंडे और बैनर लगे हुए मिले, उनकी विशेष रूप से जांच की गई। पुलिस ने ऐसे लोगों से पूछताछ की, जिनके दिल्ली जाकर प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही थी। जांच के बाद स्थिति के अनुसार लोगों को आगे जाने की अनुमति दी गई। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से जुड़े मार्गों पर नाके लगाए गए हैं।

निवेश के नाम पर 3.85 लाख रुपये ठगे, मुनाफे में दी दूसरे से ठगी गई रकम

इंदिरापुरम। नीतिखंड एक निवासी संदीप गोयल को शेयर में निवेश से मोटे मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने 3.85 लाख रुपये ठग लिए। घटना साल-2024 में हुई। मुनाफे में जो रकम दी थी वह भी ठगों ने किसी अन्य व्यक्ति से ठगी करके उनके खाते में भेज दी थी। जून 2026 में कर्नाटक कोर्ट से नोटिस मिलने पर ठगी का पता चला। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 21 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। दर्ज मामले में संदीप गोयल ने बताया कि वर्ष 2024 में अज्ञात लोगों ने उन्हें शेरखान नामक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था। इसके बाद शेयर में निवेश करने पर मोटे मुनाफे का झांसा दिया। आरोपियों ने पहले छोटे निवेश पर उन्हें मुनाफे के 60 हजार रुपये दिए। स्कोर कम होने की बात कहते हुए और निवेश के लिए फंसाया। पीड़ित ने बताया कि धीरे-धीरे उन्होंने 3.85 लाख रुपये का निवेश कर दिया। जब भी उन्हें लाभ की रकम नहीं निकालने दी गई। 8 अगस्त 2024 को उन्होंने साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 जून 2026 को उन्हें कर्नाटक के बागलकोर्ट थाने में दर्ज मुकदमे के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ। उस समय उन्हें पता चला कि मुनाफे के नाम पर उनके खाते में भेजी गई रकम साइबर ठगी की थी।

रक्त जांच में देरी से मरीज परेशान, कक्ष के बाहर भीड़ में खड़े रहने को मजबूर

फरीदाबाद, यूटर्न/ 23 जुलाई । जिला नागरिक अस्पताल में रक्त जांच कराने के लिए पहुंच रहे मरीजों को इन दिनों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जांच कक्ष के बाहर मरीजों के खड़े रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण भीड़ लगी रहती है। मरीजों का कहना है कि रक्त का नमूना देने से लेकर रिपोर्ट प्राप्त करने तक उन्हें काफी समय इंतजार करना पड़ता है। कई बार रिपोर्ट लेने के लिए भी मरीजों को अस्पताल के अलग-अलग कक्षों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे दो मरीजों ने बताया कि रक्त जांच कराने के लिए उन्हें काफी देर तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। डबुआ कॉलोनी निवासी परवेज ने बताया कि जांच के बाद रिपोर्ट मिलने में भी देरी हुई। रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए जब कर्मचारी से पूछा गया तो कभी ऊपर तो कभी नीचे जाने के लिए कहा गया। इससे मरीजों को काफी परेशानी हुई।

अब पुराने मकानों पर भी कार्रवाई की तैयारी
सात लाख संपत्तियों का सर्वे शुरू

» **फरीदाबाद, यूटर्न/ 23 जुलाई ।**

शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने अब अपनी रणनीति बदलते हुए निमार्णाधीन भवनों के साथ पहले से बने मकानों और संपत्तियों की भी जांच शुरू कर दी है। निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देश के बाद करीब सात लाख संपत्तियों का सर्वे कराया जा रहा है। इसमें भवन के वास्तविक निर्माण, स्वीकृत नक्शे और निगम रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा। प्रारंभिक आकलन के अनुसार 35 से 50 हजार संपत्तियां नियमों के उल्लंघन के दायरे में आ सकती हैं। यह कुल संपत्तियों का करीब 5 से 7 प्रतिशत बैठता है। हालांकि यह अभी अनुमानित आंकड़ा है और सर्वे पूरा होने के बाद ही वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी।

नगर निगम की कार्रवाई अब तक मुख्य रूप से निर्माण के दौरान अवैध निर्माण रोकने और मौके पर कार्रवाई करने तक सीमित रही है। अब निगम पुराने बने मकानों को भी जांच के दायरे में लाकर यह पता लगाने की तैयारी में है कि निर्माण स्वीकृत भवन योजना के अनुसार हुआ है या बाद में उसमें अतिरिक्त मंजिल, कमरा, दुकान या अन्य निर्माण किया गया है।

सर्वे में संपत्ति के रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान किया जाएगा। भवन की मंजिलों, उपयोग, स्वीकृत नक्शे से विचलन और सार्वजनिक जमीन या रास्ते पर किए गए निर्माण जैसे पहलुओं की भी जांच की जा सकती है। जहां गंभीर अनियमितता मिलेगी वहां नियमानुसार नोटिस और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

सभी मकानों पर तुरंत नहीं होगा एक्शन

इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वे में चिह्नित हर मकान को तत्काल तोड़ा जाएगा। संबंधित भवन मालिक को नोटिस, जवाब देने और नियमानुसार सुनवाई का अवसर मिलना जरूरी होगा। कार्रवाई की प्रकृति उल्लंघन की गंभीरता और लागू नियमों के आधार पर तय होगी।

सात लाख संपत्तियों का रिकॉर्ड, पहले भी सामने आ चुकी हैं खामियां

फरीदाबाद में करीब सात लाख कर योग्य संपत्ति इकाइयों का आंकड़ा पहले भी सामने आ चुका है। 2024 की उपलब्ध रिपोर्टों में शहर में करीब 7.15 लाख संपत्ति इकाइयों के पंजीकृत होने की जानकारी दी गई थी। इनमें बड़ी संख्या में संपत्ति आईडी से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी और अधूरे विवरण की शिकायतें भी सामने आई थीं। ऐसे में नए सर्वे का महत्व केवल अवैध निर्माण की पहचान तक सीमित नहीं है। इससे नगर निगम को शहर की संपत्तियों का वास्तविक और अद्यतन रिकॉर्ड तैयार करने में भी मदद मिल सकती है। खासकर ओल्ड फरीदाबाद, एनआईटी, बल्लभगढ़, गांवों से शहरी क्षेत्र में शामिल इलाकों और तेजी से विकसित हो रहे बाहरी क्षेत्रों में निर्माण की स्थिति अलग-अलग है।

पांच से सात प्रतिशत तक संपत्तियों पर कार्रवाई का अनुमान

नगर निगम से जुड़े प्रारंभिक आकलन के मुताबिक सर्वे में करीब 35 से 50 हजार मकान या संपत्तियां नियमों के उल्लंघन के दायरे में आ सकती हैं। सात लाख संपत्तियों के आधार पर देखें तो यह करीब 5 से 7 प्रतिशत का आंकड़ा बनता है। हालांकि इसे अंतिम आंकड़ा नहीं माना जा सकता। सर्वे पूरा होने और प्रत्येक संपत्ति की अलग-अलग जांच के बाद ही यह तय होगा कि कितने मामलों में वास्तव में कार्रवाई जरूरी है। यह भी संभव है कि सभी मामलों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न हो। कुछ मामलों में निर्माण को नियमों के अनुरूप करने, स्वीकृत प्रक्रिया के तहत सुधार या जहां कानून अनुमति देता है वहां कंपाउंडिंग जैसे विकल्प सामने आ सकते हैं।

जिले में भवन निर्माण के लिए हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 और नगर निगम से जुड़े नियम लागू हैं। स्वीकृत भवन योजना से अलग निर्माण और अनधिकृत निर्माण पर सक्षम प्राधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई का अधिकार है। इसलिए सर्वे के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया भी कानूनी प्रावधानों के तहत ही आगे बढ़ेगी।

सेक्टर- 29 में खारे पानी की समस्या से जूझ रहे निवासी

फरीदाबाद, यूटर्न/ 23 जुलाई । सेक्टर- 29 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में खारे पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इसके चलते निवासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को खारे पानी के चलते घरेलू कार्य करने में परेशानी हो रही है। पानी पीने योग्य नहीं है, जिसके चलते लोगों को टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है।

आरडब्ल्यूए प्रधान दीपक यादव ने बताया कि खारे पानी की समस्या वर्षों से बनी हुई है। इसको लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पेयजल समस्या के कारण महिलाओं को कपड़े धोने, बर्तन धोने व खाने बनाने में अधिक समस्या हो रही है। सुबह के समय दफ्तर जाने वाले लोगों व स्कूली बच्चों को अपने गंतव्य पर जाने में देरी होती है। लोगों को सुबह के समय टैंकरों का इंतजार करना पड़ता है। प्रतिदिन टैंकरों पर निर्भर होने से लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है।

हेड कांस्टेबल के घर से आठ लाख की चोरी

लोनी, यूटर्न/ 23 जुलाई । ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र की अंसल कॉलोनी स्थित घर घुसकर चोरों ने जेवरात और साढ़े तीन लाख रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के दौरान पीड़ित परिवार घर के दूसरे कमरे में एसी चलाकर सो रहा था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

एमएमजी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड के शौचालय की छत गिरी, बड़ा हादसा बचा

» **गाजियाबाद, यूटर्न/ 23 जुलाई ।**

एमएमजी अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में बुधवार सुबह बड़ा हादसा बच गया। वार्ड के शौचालय की छत का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। इसके साथ नीचे लगी फॉल सीलिंग भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना से वार्ड में मौजूद मरीजों व तीमारदारों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब आठ बजे भी वार्ड की छत का प्लास्टर टूटकर गिरा था। बुधवार सुबह एमएस डॉ. पंकज शर्मा और सिस्टर इंचार्ज हिना विक्टर क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान छत का बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। घटना की सूचना तत्काल सीएमएस डॉ. राकेश कुमार को दी गई।

हादसे के बाद एहतियात के तौर पर सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीजों को अस्पताल के सभागार में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रशासन ने क्षतिग्रस्त कॉरिडोर की बैरिकेडिंग कर आवाजाही रोक दी है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो।

हालांकि, इसके बावजूद कुछ मरीज और तीमारदार बैरिकेडिंग पार कर पैथोलॉजी लैब की ओर जाते दिखाई दिए। सीएमएस डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि मरीजों के उपचार में कोई बाधा न आए, इसके लिए अस्पताल में वैकल्पिक वार्ड तैयार किए जा रहे हैं।

ऑटो अप्रूवल सिस्टम के ट्रायल में बड़ी चूक, बिना टैक्स चार वाहनों का हुआ पंजीकरण

» **गाजियाबाद, यूटर्न/ 23 जुलाई ।**

परिवहन विभाग की नई ऑटो अप्रूवल व्यवस्था ट्रायल के पहले ही दिन सवालों के घेरे में आ गई। सिस्टम की खामी के कारण जिले में चार वाहनों का टैक्स जमा हुए बिना ही उनका ऑनलाइन पंजीकरण हो गया। मामला सामने आते ही परिवहन विभाग ने शासन स्तर पर इसकी जानकारी दी। इसके बाद ऑटो अप्रूवल से निस्तारित फाइलों को तत्काल ब्लॉक करा दिया गया।

नई व्यवस्था का ट्रायल सोमवार को शुरू हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि डीलरों ने चार वाहनों का टैक्स जमा कराए बिना ही ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर दी। पंजीकरण की सुविधा डीलर प्वाइंट से ही उपलब्ध है, इसलिए टैक्स जमा न होने के बावजूद आवेदन जनरेट हो गया और सिस्टम ने उसे स्वतः मंजूरी भी दे दी। गड़बड़ी सामने आने के बाद परिवहन विभाग ने दो दिनों में ऑटो अप्रूवल से निस्तारित सभी फाइलों को ब्लॉक करा दिया। वहीं, एनआईसी ने भी बिना टैक्स वाले मामलों का ऑटो अप्रूवल निरस्त करते हुए संबंधित आवेदनों को स्थानीय आरटीओ कार्यालय भेज दिया, ताकि निर्धारित टैक्स जमा कराने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। आरटीओ प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में अभी शासन स्तर पर परीक्षण और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

टीनशेड की आड़ में फिर बसीं झुग्गियां, तार डालकर हो रही बिजली आपूर्ति

» **साहिबाबाद, यूटर्न/ 23 जुलाई ।**

कनावनी में 16 अप्रैल को आग से 150 झुग्गियां राख होने के बाद भी जिम्मेदारों ने सबक नहीं लिया। महज कुछ ही दिनों में उसी जमीन पर एक बार फिर झुग्गियां बस गई हैं। टीनशेड की आड़ में कबाड़ के गोदाम बनाए गए हैं और बिजली कनेक्शन से आपूर्ति भी बहाल कर दी गई है। हैरानी की बात यह है कि बिजली के मीटरों को चादर से ढककर छिपाया गया है, जबकि टीनशेड की दीवारों से पूरे इलाके को घेर दिया गया है।

कनावनी में बड़े कबाड़ गोदाम बनाकर मोटा किराया वसूला जा रहा है। पिछले हादसे में जिन लोगों की झुग्गियां जलकर राख हो गईं, उन्हीं में से कई परिवार दोबारा यहां बस गए हैं। करीब तीन हजार रुपये प्रतिमाह किराया और बिजली खर्च भी इनसे वसूला जा रहा है। एक तरफ जहां लोग खुद भी जान को जोखिम में डाल रहे हैं वहीं ,दूसरी ओर जिम्मेदारों ने भी आंख मूंद ली हैं। उनकी नाक के नीचे दोबारा बिजली चोरी का खेल शुरू हो गया और कार्रवाई करने की जरूरत तक नहीं समझी जा रही है। यह सिलसिला सिर्फ कनावनी तक सीमित नहीं है।

वैशाली सेक्टर तीन में मई माह में आग लगने से करीब 20 झुग्गियां जलकर राख हो गई थीं, लेकिन लोगों ने दूसरे प्लॉट पर बसावट शुरू कर दी है। वहां ई-रिक्शा पार्किंग और कबाड़ गोदाम बन चुका है। इंदिरापुरम, कौशांबी, टीलामोड़ और साहिबाबाद सहित अन्य इलाकों में पहले भी इसी तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन हालात बदले नहीं हैं। सात माह में 300 से अधिक झुग्गियां आग हादसों में जल चुकी हैं। इसके बावजूद सैकड़ों परिवार अपनी जान की चिंता किए बिना बिजली के खुले तारों और टीनशेड की तंग गलियों में जीवन गुजार रहे हैं। अवैध कब्जे और बिजली आपूर्ति की इन घटनाओं पर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अब तक पूरी नहीं हुई पहले हादसे की जांच

16 अप्रैल को कनावनी आग हादसे के बाद ऊर्जा निगम ने जांच शुरू की थी। जांच में झुग्गियों में कनेक्शन देने के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम भी सामने आए जो वर्तमान में दूसरे जिले में तैनात हैं। उनके बयान अब तक दर्ज नहीं हुए हैं।

इशन्या ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा कि सन किस्ड और बेफिक्री। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा कि टू हॉट। दूसरे ने लिखा- किलर। कई लोगों ने उनके लुक को फायर बताया है।

बिकिनी में नजर आई इशन्या माहेश्वरी

पूल में दिए सिजलिंग पोज, फैन्स हारे दिल

इशन्या माहेश्वरी साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। इशन्या सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं और अपने फैन्स को सरप्राइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। इन दिनों इशन्या वेकेशन पर हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर बोल्ड फोटोज शेयर की हैं, जिस पर फैन्स अपना प्यार लुटा रहे हैं। फोटोज में इशन्या माहेश्वरी येलो कलर की पोल्का डॉट बिकिनी में पूल किनारे पोज देती दिख रही हैं।

एक फोटो में इशन्या स्विम करती नजर आईं। बिकिनी में वो बोल्ड और सेंशुअस पोज देती दिखीं। इशन्या की कातिलाना अदाएं फैन्स को घायल कर रही हैं। एक्ट्रेस का फैशन स्टाइल मॉर्डन और क्लासिकल था, जिसे देखकर पता चल रहा है कि उन्हें फैशन की अच्छी खासी समझ है। वेकेशन पर इशन्या लग्जरी रिजॉर्ट में ठहरी हैं, जहां वो पूल किनारे चिल करती नजर आईं। उन्हें देखकर बस यही लग रहा है कि वेकेशन हो, तो ऐसा। इशन्या ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा कि सन किस्ड और बेफिक्री। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा कि टू हॉट। दूसरे ने लिखा- किलर। कई लोगों ने उनके लुक को फायर बताया है।

सना सईद ने बयां किया अपना दर्द

शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म कुछ-कुछ होता है में बाल कलाकार के रूप में नजर आ चुकीं अभिनेत्री सना सईद ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक भावुक खुलासा किया है। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी आलिया भट्ट के साथ अहम भूमिका निभा चुकीं सना ने अपनी जिंदगी के उस कठिन दौर के बारे में खुलकर बात की, जिससे उबरने में उन्हें काफी समय लगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि उन्हें सालों तक पता ही नहीं चला कि उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर बुलिमिया नवोर्सा है। सना ने बताया, ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं परेशान नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मैंने कभी इन शब्दों के बारे में सुना ही नहीं था। बड़े होते हुए किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो हो रहा था, उसे बताने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे, इसलिए उन्होंने लंबे समय तक इसे चुपचाप और अकेले ही सहा। जब उन्होंने आखिरकार बुलिमिया के बारे में पढ़ा, तब उन्हें पहली बार समझ आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बावजूद, इसे स्वीकार करने की शर्म झ खुद से भी झ को दूर करने में उन्हें सालों लग गए।

आंचल सिंह की सगाई

वेब सीरीज ये काली काली आंखें से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री आंचल सिंह ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी फैंस के साथ साझा की है। उन्होंने अपने लंबे समय से रहे बॉयफ्रेंड मोहित चावला के साथ सगाई कर ली है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस समारोह को लेकर शादी की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन आंचल ने खुद स्पष्ट किया कि यह उनकी शादी नहीं बल्कि सगाई का समारोह था। आंचल सिंह के मंगेतर मोहित चावला पेशे से एक बिजनेसमैन हैं और दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में हैं। आंचल ने अपनी इंगेजमेंट की कई खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिन्हें फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है। इन तस्वीरों में उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। इन तस्वीरों में आंचल ने गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना हुआ है, जिसके साथ उनकी हैवी ज्वेलरी काफी आकर्षक नजर आ रही है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश टीम का हिस्सा नहीं होंगे इबादत हुसैन

» ढाका, यूटर्न/ 23 जुलाई ।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले महीने होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज इबादत हुसैन हिस्सा नहीं लेंगे। इबादत की पत्नी गर्भवती हैं और वह जल्द ही पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। इसी कारण इबादत इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 13 अगस्त से होना है। सीरीज का पहला मुकाबला डार्विन में खेला जाना है।

वहीं, दूसरे टेस्ट मुकाबले की शुरूआत 22 अगस्त से होगी। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। आईसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी के लिए लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) से अपना नाम वापस ले लिया है। तस्कीन को एलपीएल में जाफना किंग्स की तरफ से खेलना था, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है।

तस्कीन ने 'द डेली सन' से बातचीत में बताया कि उन्होंने यह फैसला मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी को ध्यान में रखते हुए लिया है। उन्होंने कहा, 'हमने जिम्बाब्वे में लगातार छह मैच खेले थे। अगर मैं वहां से

लौटकर तुरंत ऑस्ट्रेलिया चला जाता, तो शायद मुझे एलपीएल में सिर्फ चार मैच खेलने का मौका मिलता। इससे मेरी टेस्ट मैचों की तैयारी प्रभावित हो सकती थी।' तस्कीन ने बताया कि भले ही एलपीएल से हटने के कारण उन्हें कुछ नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उन्हें लगा कि यह सही फैसला है। उनके मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बार-बार खेलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) मिलने के बावजूद एलपीएल में नहीं खेलने का फैसला किया, ताकि वह ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पूरी तरह तैयार रह सकें।

बचपन के कोच को कुलदीप की टीम में वापसी का भरोसा

» मुम्बई, यूटर्न/ 23 जुलाई ।

जब भी अवसर मिलेगा अपने को साबित करेगा

स्पिनर कुलदीप यादव के बचपन के कोच कपिल पांडे ने कहा है कि इंग्लैंड दौरे में अवसर नहीं मिलने से कुलदीप निराश नहीं है और उसका मनोबल जरा भी कम नहीं हुआ है। कोच के अनुसार टीम चयन का अधिकार कप्तान और कोच का रहता है और ऐसे में कोई भी खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता। केवल अपनी ओर से प्रयास भर कर सकता है। कोच के अनुसार कुलदीप बेहद जुझारू हैं और वह टीम में जरुर वापसी करेगा। ये भी कहा देखा गया है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारतीय टीम ने 104 मैच खेले हैं पर कुलदीप इनमें से केवल 38 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ही खेल पाए हैं। इसके बाद से ही गंभीर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं पर कुलदीप के कोच का कहना है कि टीम चुनना कप्तान और कोच का काम है। पांडे ने स्पष्ट किया, कुलदीप के निराश होने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने अच्छी तैयारी की है और जब भी उन्हें मौका मिला है, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पांडे के लिए, कुलदीप का भारतीय टीम का हिस्सा बने रहना ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा, जब टीम हारती है तो हमेशा दुख होता है पर सबसे बड़ी बात भारतीय टीम का हिस्सा बने रहना है। देश के लिए खेलना गर्व की बात है।

उकके अनुसार कुलदीप अब भी प्रमुख स्पिनर बने हुए हैं और जब भी उन्हें मौका मिलेगा, वे तुरंत अपना प्रभाव दिखाएंगे। पांडे ने इस बात को भी गलत बताया कि कुलदीप के कम टेस्ट मैच खेलने से उनकी योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि असल मायने में उनका मैच जिताने वाला प्रभाव मायने रखता है। कुलदीप ने अपने डेब्यू के बाद साढ़े नौ साल में केवल 18 टेस्ट मैच खेले हैं। पांडे ने इस पर जोर देते हुए कहा, बात यह नहीं है कि उन्होंने कितने टेस्ट खेले हैं, बल्कि यह है कि उन मैचों में उन्होंने कैसा असर डाला है। जब भी कुलदीप खेले हैं, उन्होंने भारत को जीत दिलाने में मदद की है। साल 2024 में घर पर इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वह एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धी हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुलदीप के एकदिवसीय रिकॉर्ड से हमेशा पता चला है कि जब उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, तो वह शानदार प्रदर्शन करते हैं, चाहे उन्होंने कितने भी मैच खेले हों। पांडे ने यह भी बताया कि कुलदीप की बल्लेबाजी में हुए सुधार पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। उन्होंने कहा, अगर आप कुलदीप की बल्लेबाजी देखें, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए एक शतक और कई अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने अपने खेल के इस पहलू पर भी कड़ी मेहनत की है। कोच ने यह भी बताया कि एक स्थापित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बनने के बावजूद कुलदीप की काम करने की लगन में कोई बदलाव नहीं आया है। कोच ने कहा, चाहे आईपीएल के बाद हो या किसी अंतरराष्ट्रीय सीरीज के बाद, वह सीधे कानपुर में हमारी अकादमी में वापस आते हैं। विदेश दौरों से पहले भी वह यहीं ट्रेनिंग करते हैं और अभ्यास मैच खेलते हैं।

यूटर्न टाइम
THE GOOD, BAD & UGLY OF INDIA

भारी बारिश और फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, खैबर पख्तूनख्वा में 18 की मौत

» इस्लामाबाद, यूटर्न/ 23 जुलाई ।

पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड ने बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत में 19 जुलाई से अब तक बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई जबकि 19 अन्य घायल हुए हैं। यह जानकारी प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) ने गुरुवार को दी।

पीडीएमए के अनुसार, अधिकांश मौत मकानों की छत या दीवार गिरने और लोगों के फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से हुईं। मृतकों में आठ बच्चे, सात पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। वहीं, घायलों में 11 पुरुष, चार महिलाएं और चार बच्चे हैं।

बारिश और बाढ़ से 30 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 23 आंशिक रूप से और सात पूरी तरह से नष्ट हो गए। बारिश से जुड़ी घटनाएं बुनैर, स्वाबी, मर्दान, बाजौर, शांगला, लोअर चितराल, पेशावर, नौशेरा, खैबर, लोअर और अपर दीर, एबटाबाद, मानसेहरा, तोर घर, कुर्रम तथा उत्तर और दक्षिण वजीरिस्तान सहित कई जिलों में दर्ज की गई हैं।

पीडीएमए ने बताया कि रेस्क्यू 1122, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान जारी है।

उधर, पंजाब प्रांत के गुजरांवाला, नारोवाल, पाकपत्तन और लाहौर में भी बारिश से जुड़ी घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हुए हैं। सबसे अधिक प्रभावित गुजरांवाला रहा, जहां मकानों की छत और दीवार गिरने, तालाबों में डूबने और करंट लगने जैसी घटनाओं में छह लोगों, जिनमें अधिकांश बच्चे थे, की जान चली गई। वहीं, पाकपत्तन में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई और उनकी मां घायल हो गई।

यूएन में बलूचिस्तान मुद्दे पर भारत बोला- संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों को मिले न्यायसंगत हिस्सा, तभी रुकेगी अस्थिरता

» संयुक्त राष्ट्र, यूटर्न/ 23 जुलाई

भारत ने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के कथित शोषण का मुद्दा उठाया है। भारत का कहना है कि खनिज और अन्य प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध बलूचिस्तान का लंबे समय से दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण वहां के लोगों में इस्लामाबाद के खिलाफ असंतोष और विद्रोह की भावना बढ़ी है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने बुधवार को कहा, 'यह प्रत्येक देश की जिम्मेदारी है कि तेल और गैस, खनिज, दुर्लभ धातुओं और बहुमूल्य संसाधनों से समृद्ध प्रांतों को उन संसाधनों से होने वाले लाभ में न्यायसंगत और समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करे।'

उन्होंने कहा कि ऐसा करना केवल संबंधित देश के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में आंतरिक अस्थिरता और असुरक्षा को रोकने के लिए भी आवश्यक है।

पी. हरीश ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कूटनीतिक अंदाज में संकेत दिया कि यह स्थिति बलूचिस्तान पर लागू होती है। उन्होंने कहा, 'ऐसा न करने के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिनका। प्रभाव हमारे क्षेत्र में भी देखा जा सकता है।' प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने के बावजूद बलूचिस्तान आज भी देश के सबसे गरीब प्रांतों में से एक बना हुआ है।

इसकी वजह से बलूच के लोगों ने अपने प्रांत के योगदान में सही हिस्सा मांगते हुए विरोध प्रदर्शन किए और उनके बेरहमी से दबाने से बगावत को बढ़ावा मिल रहा है।

हरीश ने चेतावनी दी, 'संसाधनों से भरपूर प्रांतों के शासन में सख्ती और सुरक्षा वाला तरीका मामलों को और खराब करता है। जो प्रांत संसाधनों से भरपूर हैं लेकिन विकास में पिछड़े हैं, वे असुरक्षा का केंद्र बन जाते हैं जो अपनी सीमाओं के बाहर, यहां तक कि पड़ोसी देशों में भी अस्थिरता फैलाते हैं।'

संक्षिप्त खबरें

अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता

वाशिंगटन, यूटर्न/ 23 जुलाई। ईरान के साथ जारी भीषण तनाव के बीच अमेरिका और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अगले 30 वर्षों के लिए लागू होने वाले इस अरबों डॉलर के समझौते को मंजूरी दे दी। इस डील के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में असैन्य परमाणु संयंत्र स्थापित करने और तकनीक हस्तांतरण में मदद करेंगी। हालांकि, इस समझौते ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और रक्षा विशेषज्ञों के बीच भारी हलचल मचा दी है, क्योंकि अमेरिका ने पारंपरिक सुरक्षा मानकों को दरकिनार करते हुए इसमें परमाणु हथियार बनाने से रोकने वाले सख्त नियम शामिल नहीं किए हैं। सामान्य तौर पर, जब भी अमेरिका किसी देश को परमाणु तकनीक मुहैया कराता है, तो वह यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) और प्रयुक्त ईंधन के पुनर्संस्करण पर सख्त प्रतिबंध लगाता है।

ईरान ने अमेरिका को दी 9/11 जैसे हमले की धमकी

तेहरान, यूटर्न/ 23 जुलाई । अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अब धमकियों का दौर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के प्रमुख बुनियादी ढांचे पर बमबारी की चेतावनी दिए जाने के बाद, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने अमेरिका को वर्ष 2001 में हुए 9/11 जैसे विनाशकारी हमले की सीधी धमकी दी है। आईआरजीसी ने स्पष्ट कहा है कि यदि अमेरिका ने अपने हमले तुरंत नहीं रोके, तो उस पर ऐसा बड़ा हमला किया जाएगा जिससे अमेरिका में पुनः राष्ट्रीय शोक की स्थिति पैदा हो जाएगी और उसे अपने कदमों पर पछताना पड़ेगा। इस धमकी से पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों से बेहद क्रुद्ध नजर आए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी कि यदि ईरान ने होर्मुज मार्ग में किसी भी जहाज पर मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट से हमला किया.

शी की वाशिंगटन यात्रा की तैयारियां तेज, बड़े मतभेदों पर होगी चर्चा : मार्को रूबियो

» वाशिंगटन, यूटर्न/ 23 जुलाई

अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो ने कहा है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ उनकी लंबी मीटिंग सितंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अमेरिकी दौरे के लिए ग्राउंडवर्क तैयार करने पर केंद्रित थी। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बड़े रणनीतिक अंतर के बावजूद वाशिंगटन और बीजिंग को बातचीत जारी रखनी चाहिए। मनीला में आसियान से जुड़ी बैठकों के इतर बुधवार (वाशिंगटन समयानुसार) पत्रकारों से बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि चीन के साथ हुई लंबी बैठक का कारण दोनों पक्षों के बीच किसी तरह का तनाव नहीं, बल्कि अनुवाद में लगा समय था।

रुबियो ने कहा, 'हमने सितंबर में होने वाली यात्रा पर काफी विस्तार से चर्चा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य इसी दौरे की तैयारी करना था, ताकि यह एक और सकारात्मक यात्रा साबित हो। मेरा मानना है कि जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग वाशिंगटन आएंगे तो उनकी यात्रा बेहद सकारात्मक रहेगी।' एक सवाल के जवाब में रुबियो ने अमेरिका और चीन को दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं और प्रमुख देश बताया। उन्होंने कहा कि गंभीर मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, 'हमारे बीच संबंध बने रहना आवश्यक है। कई मुद्दों पर हमारे बड़े मतभेद हैं और दोनों पक्ष इसे स्वीकार करते हैं। हमें इन मतभेदों को संभालना होगा। मेरा मानना है कि ये मतभेद निकट भविष्य में भी बने रहेंगे और हमारी जिम्मेदारी है कि इन्हें इस तरह प्रबंधित किया जाए कि स्थिति कभी नियंत्रण से बाहर न जाए।'

अमेरिकी विदेश सचिव रुबियो ने कहा कि सितंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले दोनों देशों के अधिकारी ऐसे क्षेत्रों की पहचान करेंगे, जहां सहयोग संभव है, ताकि बैठक के दौरान ठोस और व्यावहारिक परिणाम सामने लाए जा सकें। रुबियो ने कहा कि दोनों पक्षों ने पहले की मीटिंग में तय हुए तरीकों को लागू करने पर भी चर्चा की, जिसमें व्यापार और निवेश की पहल शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'हम इसे लागू करने की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि यह उन ठोस नतीजों में से एक है जो हम सितंबर से पहले कर सकते हैं।'

हाल ही में अमेरिका की ट्रंप सरकार ने दावा किया कि 2020 के अमेरिकी चुनाव में चीन ने हस्तक्षेप किया था। इसे लेकर सवाल पूछे जाने पर रुबियो ने छोटा सा जवाब दिया, 'हमने उस मुद्दे पर चर्चा नहीं की।' ताइवान के बारे में, रुबियो ने कहा कि यह मुद्दा चीनी अधिकारियों के साथ हर मीटिंग में इसलिए उठा क्योंकि वाशिंगटन ने द्वीप के आसपास बीजिंग की सैन्य गतिविधियों का विरोध किया था।

श्रीलंकाई नौसेना ने नौ भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, ट्रॉलर भी जब्त

चेन्नई, यूटर्न/ 23 जुलाई । श्रीलंकाई नौसेना ने नौ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उनके मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर को जब्त कर लिया। मछुआरों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन (आईएमबीएल) पार की और श्रीलंकाई पानी में गैरकानूनी तरीके से मछली पकड़ी। इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में एक और मामला जुड़ गया है। श्रीलंकाई नेवी के मुताबिक, ये गिरफ्तारियां एक समुद्री निगरानी और कार्रवाई के दौरान की गईं, जब नेवी के लोगों ने श्रीलंकाई पानी में भारतीय मछली पकड़ने वाली नावों के एक बड़े समूह का पता लगाया। खबर है कि मछुआरों को तलाईमन्नार के उत्तर में बिना इजाजत के द्वीप देश के पानी में घुसने के बाद पकड़ा गया।

कांगो में हिंसा के बीच इबोला से जंग पर संकट, संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता

» संयुक्त राष्ट्र, यूटर्न/ 23 जुलाई

संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) के नॉर्थ किवु प्रांत में असुरक्षा के कारण मानवीय कार्यों पर असर पड़ रहा है, जिसमें इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयास भी शामिल हैं। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बुधवार (स्थानीय समय) को एक दैनिक ब्रीफिंग में कहा कि स्थानीय नागरिक समाज संगठनों के अनुसार, 13 से 19 जुलाई के बीच प्रांत के बेनी इलाके में हुए कई हमलों में कम से कम 30 लोग मारे गए और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हिंसा के कारण आम लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और प्रभावित इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचाने में रुकावट आ रही है। डुजारिक ने संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय का हवाला देते हुए कहा कि सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति के कारण, इबोला से निपटने में मदद करने वाले सहयोगियों सहित कम से कम छह मानवीय संगठनों ने बेनी इलाके के कई इलाकों में अपनी आवाजाही रोक दी है।

ईरान समझौते के लिए अभी तैयार नहीं पर जल्द ही तैयार हो जाएगा : ट्रंप

» वॉशिंगटन, यूटर्न/ 23 जुलाई

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारी सैन्य दबाव झेलने के बावजूद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता करने के लिए अभी तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि तेहरान लगातार बातचीत के दौरान अपना रुख बदलता रहा, जबकि अमेरिका अपने इस संकल्प पर कायम है कि वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ईरान के साथ संघर्ष में मारे गए चार अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) जॉर्जिया में एक चुनावी रैली जैसी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तेहरान के प्रति अपनी सरकार की सैन्य और कूटनीतिक नीति का बचाव किया और इस टकराव को दुनिया में अमेरिका की ताकत बहाल करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बताया।

ट्रंप ने कहा, 'शेयर बाजार लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। मैं ईरान के इस टकराव को एक छोटी झड़प कहता हूं।

इसके बावजूद चुनाव के बाद से शेयर बाजार 73 बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है।' उन्होंने इस सैन्य तनाव को अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था और निवेशकों के भरोसे से जोड़कर पेश किया।

ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि तेहरान अभी भी किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, 'उन पर जबरदस्त दबाव है और वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन हर बार जब समझौते की बात होती है तो वे अपनी शर्तें बदल देते हैं। वे अभी तैयार नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे।'

Owner, Publisher, Printer: - Komal Sharma, C/O Ummpl Marketing Pvt. 194-G, Sector 63, Noida 201307, Editor: Sandeep Sharma
Contact - +91 9888200619

* तमाम प्रकाशित सामग्री के चयन व संपादन हेतु आर.बी.एक्ट. के तहत जिम्मेवार *